

रीवा हवाई अड्डा

चर्चा में क्यों

हाल ही में मध्य प्रदेश के **रीवा** हवाई अड्डे को <u>नागरिक विमानन महानिदेशालय (Directorate General of Civil Aviation DGCA)</u> से परिचालन लाइसेंस की मंजूरी मिली, जो क्षेत्रीय संपर्क और आर्थिक विकास को बढ़ाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

मुख्य बदुि

- रीवा के जुड़ने के साथ ही मध्य प्रदेश में अब छह हवाई अड्डे हो गए हैं,अन्य भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और खजुराहो में स्थित हैं
 - रीवा अपने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों के लिये जाना जाता है तथा हवाई अड्डा इन आकर्षणों को अधिक सुलभ बना देगा, जिससे संभवतः अधिक आगंतुक एवं व्यवसाय आकर्षित होंगे।
- इस हवाई अड्डे का विकास प्रधानमंत्री के 'विकसित भारत-विकसित मध्य प्रदेश' के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो यह सुनिश्चित करता है कि
 यह विध्य क्षेत्र के विकास के लिये आधारशिला बने ।

विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश के अंतर्गत प्रमुख प्रयोजनाएँ

- सिचाई परियोजनाएँ: ऊपरी <u>नर्मदा</u> परियोजना, राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना, <mark>बसनिया बहुउद्</mark>देशीय परियोजना (5500 करोड़ रुपए) ।
- सूक्ष्म सिचाई परियोजनाएँ: पारसदोह सूक्ष्म सिचाई परियोजना, औलिया सूक्ष्म सिचाई <mark>परि</mark>योजना (८०० करोड़ रुपए) ।
- रेलवे परियोजनाएँ: वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी-जाखलौन मार्ग पर तीसरी लाइन परियोजनाएँ, गेज परिवर्तन परियोजना, पवारखेड़ा-जुझारपुर रेल लाइन फ्लाईओवर (2200 करोड़ रुपए)।
- औद्योगिक परियोजनाएँ: सीतापुर में मेगा लेदर और फुटवियर क्लस्टर, इंदौर में गारमेंट इंडस्ट्री प्लग एंड प्ले पार्क, औद्योगिक पार्क मंदसौर, पीथमपुर औद्योगिक पार्क का उन्नयन (1000 करोड़ रुपए)।
- कोयला क्षेत्र की परियोजनाएँ: जयंत OCP CHP साइलो, एनसीएल सिगरौली; दुधिचुआ OCP CHP-साइलो (1000 करोड़ रुपए)।
- विद्युत क्षेत्र: पन्ना, रायसेन, छिदवाड़ा और नर्मदापुरम ज़िलों में छह सबस्टेशन।
- जल आपूर्ति परियोजनाएँ: विभिन्न अमृत 2.0 परियोजनाएँ, खरगोन में जलापूर्ति वृद्धि (880 करोड़ रुपए)।
- **साइबर तहसील परियोजना:** राजस्व अभिलेखों और बिक्री-खरीद अभिलेखों के उत्परविर्तन में डिजिटिल समाधान के लिये 55 ज़िलों में शुरू की गई।

नागरिक विमानन महानदिशालय (DGCA)

- यह नागरिक उड्डयन मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है।
- यह नागरिक विमानन के क्षेत्र में नियामक संस्था है जो मुख्य रूप से सुरक्षा मुद्दों से निपटती है।
- यह भारत के लिये/से/भारत के भीतर हवाई परविहन सेवाओं के विनियमन और नागरिक हवाई विनियमों, हवाई सुरक्षा एवं उड़ान योग्यता मानकों के प्रवर्तन के लिये जिम्मेदार है।
- यह अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन के साथ सभी विनियामक कार्यों का समन्वय भी करता है ।